तबाही की गवाही

डॉ. विजय कुमार
विभागाध्यक्ष, गांधी विचार विभाग, भागलपुर विश्वविद्यालय

18 अगस्त 2008 को कुसहा पर तटबंध टूटने के साथ ही कोशी की बाढ़ ने उत्तर बिहार के आठ जिलों में बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी। कुसहा में तटबंध टूटने की परिस्थितियों ने यह साफ कर दिया कि तटबंध लापरवाही और भ्रष्टाचार की वजह से टूटा। यानी यह भी कहा जा सकता है कि वह टूटा नहीं, बल्कि तोड़ा गया। इससे हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, जो पिछले तीन दशक में बिहार में सक्रिय रहे हैं, बेचैन थे। हमें महसूस हुआ कि पिछले 45 साल से कोशी सरकारी भ्रष्टाचार और गैर जिम्मेदारी के जिन रास्तों के बीच कैद थी, उससे निकल कर वह उन इलाकों में बहने लगी, जिन्हें बाढ़ मुक्त मान लिया गया था। मात्र डेढ़ लाख क्यूसेक पानी कोशी में बाढ़ पैदा नहीं करती। इसके बावजूद अगर उतने ही पानी से इतनी बड़ी तबाही हुई तो यह साफ है कि इसे प्रलय या कोशी का कहर कहकर नहीं टाला जा सकता। हमने महसूस किया कि इसके पीछे की इंसानी वजहों को उजागर करना जरूरी है।

एक तरफ सरकारी लापरवाही ने इतनी बड़ी आपदा ला दी, दूसरी तरफ विपत्ति के दौर में लोगों को राहत पहुंचने में भी सरकारी अमला बिल्कुल नाकाम साबित हुआ। मौके पर पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ता सरकारी बचाव और राहत कार्यों की ढिलाई देख कर दंग रह गए।

हम लोगों ने महसूस किया कि इस मानवीय त्रासदी के अनछुए पहलुओं को महज सरकारी आंकड़ों से नहीं समझा जा सकता। इसलिए हमने कोशी में नाव यात्रा निकालने का फैसला किया। इस यात्रा का नाम रखा- तबाही की गवाही। नाव यात्रा 11 अक्टूबर 2008 को वीरपुर शुरू हो कर 21 अक्टूबर को कुरसेला में पूरी हुई। नाव यात्रा के दौरान प्रभावित इलाकों में हम ठहरते हुए चले और पीड़ितों से मिले। हमने पिछले 45 साल के उन संदर्भों को समझने की कोशिश की जिनका संबंध सत्ता और समाज से है। नाव यात्रा में कुल 19 साथी शामिल हुए। इनमें पांच पूर्व इंजीनियर थे।

कोशी परियोजना में काम कर चुके पूर्व इंजीनियर साथियों ने बताया कि उन्होंने तीन से चार लाख क्यूसेक पानी का बहाव देखा है। एपलक्स बांध नौ लाख क्यूसेक पानी धारण करने की क्षमता रखता है। अगर एक या डेढ़ लाख क्यूसेक पानी से यह टूट जाए तो इसे लापरवाही का परिणाम ही कहा जाएगा।

इंजीनियरों ने बताया कि बिहार सरकार के अपने निर्देशों के मुताबिक बाढ़ नियंत्रण के काम हर साल 30 अप्रैल तक पूरे हो जाने चाहिए। इसके बाद स्थिति पर नजर रखी जाती है और स्थिति की गंभीरता के मुताबिक आगे प्रबंधन कार्य किया जाता है। कुसहा में आखिर ये उपाय क्यों कारगर नहीं रहे, अगस्त 2008 की बाढ़ एक बड़ा सवाल छोड़ गई। आखिर कोई बांध अचानक नहीं टूटता। पहले कई दिनों से मिट्टी का कटाव शुरू होता है। अगर लगातार निगरानी की व्यवस्था हो तो इसका पता चल सकता है। कुसहा में भी कटाव जरूर पहले से शुरू हुआ होगा और ड्यूटी पर तैनात इंजीनियरों को इसकी जानकारी होगी। स्थानीय लोगों ने बताया कि तटबंध का कटाव एक महीने पहले शुरू हो गया था।

तबाही की गवाही यात्रा के दौरान हमने पाया कि कोशी तटबंध टूटने के बाद नदी की स्वतंत्र धारा का निर्माण नहीं सका, इसकी वजह से 85 दिन बाद भी नदी की धारा 20 से 30 किलोमीटर की चौड़ाई में फैली हुई थी। बलुआ से चैनपुर के बीच कहीं कहीं धारा खेतों को 10 से 15 फीट गहरा करते हुए बह रही थी।

जिस समय बाढ़ आई खेत धान की फसल से भरे थे। जूट की फसल कटने को तैयार थी। ये सब कुछ बाढ़ में समा गया। पशु धन का भारी नुकसान हुआ। लोगों ने बताया कि 70 फीसदी पशु बाढ़ की भेंट चढ़ गए।

गांवों में दलित बस्तियों को कुछ ज्यादा ही नुकसान हुआ। वजह यह है कि अक्सर दलितों के टोले गांवों के निचले हिस्सों में होते हैं।

राहत और बचाव कार्य का हाल यह रहा कि बाढ़ आने के दो महीने बाद तक राहत सामग्री लाने के लिए कई जगहों तक नावों की व्यवस्था नहीं हो सकी। राहत सामग्रियों का वितरण लोगों के निवास से काफी दूर, कई बार तो पांच किलोमीटर तक होता था। बाढ़ के दो महीने बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से राशन मिलना बंद हो गया। इस बीच गांवों के स्कूलों में पढ़ाई लिखाई लगभग ठप ही रही। मध्याह्न भोजन योजना पूरी तरह बंद हो गई। प्रशासन पंगु पड़ा रहा और चोर-डकैतों की बन आई। सेना

के जवानों ने जरूर लोगों की मदद की, लेकिन राज्य प्रशासन लाचार दिखता रहा। नहर और यातायात व्यवस्थाएं छिन्न-भिन्न हो गईं। इस तबाही ने कोशी इलाके के लोगों का बांध और तटबंधों से मोह भंग कर दिया है। यह धारणा बन गई है कि ऐसे उपायों से कोशी को कैद नहीं रखा जा सकता। तबाही के गवाह बनने के बाद हमारी भी राय बनी कि कोशी की बाढ़ का पर्यावरण सम्मत, प्रकृति उन्मुख, भूगर्भशास्त्रीय हल ढूंढा जाए। जल निकास (ड्रेनेज) में पड़ी बाधाओं ने समस्या को और गंभीर बना दिया है, इसलिए यथासंभव प्राकृतिक व्यवस्था बहाल करने की कोशिश की जाए। दरअसल, तबाही की गवाही यात्रा के दौरान कई मांगें सामने आईं, जो संलग्नक में 'आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेप एवं जवाबदेही की सुनिश्चितता' दस्तावेज में दर्ज हैं।
तबाही की गवाही यात्रा की पूरी रिपोर्ट संलग्न है। ***(संलग्नक- 1)***

तबाही की गवाही की इस यात्रा के समाप्त होने पर एक सार्वजनिक सभा में इसकी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया। यह निर्णय भी लिया गया कि एक ज्ञापन तैयार करके दिसंबर 2008 के अंत तक राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाए। कई कारणों से यह ज्ञापन राष्ट्रपति को नहीं दिया जा सका। ***(संलग्नक-2)***

फरवरी 2009 में गांधी विचार विभाग के विद्यार्थियों ने एक शोध शिविर के अंतर्गत बसंतपुर प्रखंड के कई गांवों में तबाही की स्थिति का अध्ययन किया। शोध शिविर के अंत में बलुआ बाजार में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग दस हजार लोगों ने हिस्सा लिया। इस सभा में एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसको बलुआ प्रस्ताव का नाम दिया गया। यह प्रस्ताव इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है। ***(संलग्नक-3)***

इन मांगों को लेकर जन कार्रवाई की योजना बनी है। इसी के तहत सहरसा में अक्टूबर 2009 में मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन **कोशीवासी** के नाम से सौंपा गया। ***(संलग्नक-4)***

अब सामाजिक कार्यकर्ताओं और जन आंदोलनों के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाने की कोशिश जारी है। इसी सिलसिले में इस साल दिसंबर में एक सात दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। इसमें भाग लेने वाले ज्यादातर कार्यकर्ता ऐसे हैं जो बिहार में 20 साल से ज्यादा सक्रिय रहे हैं। इस संदर्भ में एक पृष्ठभूमि पत्र तैयार किया गया है। ***(संलग्नक-5)***

अगस्त 2008 से अक्टूबर 2009 तक अनेक महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठनों से संवाद की प्रक्रिया जारी रही।

इसमें से मुख्य है- वैज्ञानिक एवं तकनीकीविद् मंच, पटना द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज, जिसमें जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार के सभी प्रमाण विस्तार से दर्शाए गए हैं। इस समूह के कई इंजीनियर हमारे साथ तबाही की गवाही यात्रा में भी शामिल रहे। यह पूरा दस्तावेज हमारे कार्यालय में संदर्भ के रूप में उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त श्री जगन्नाथ मिश्र के मानव अधिकार सरंक्षण प्रतिष्टान द्वारा कुसहा टूट के कारणों पर विचार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया और इसके द्वारा अनेक दस्तावेज तैयार किए गए। बाद में एक तकनीकी कमेटी का गठन किया गया, जिसने कोशी तटबंध से जुडे सभी पहलुओं पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। इस कमेटी के चेयरमैन थे- श्री गोकुल प्रसाद जो पहले केंद्रीय जल आयोग के चेयरमैन भी रह चुके हैं। ये सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज भी हमारे कार्यालय में संदर्भ के रूप में उपलब्ध हैं।

मैं सैडेड के साथ जुड़ा रहा हूं और नाव यात्रा में सैडेड का पूरा सहयोग रहा। आगे हो रही जन-कार्रवाइयों में भी सैडेड की मुख्य भूमिका है। इसके सहयोग से ही आगे की रणनीति तय करने और उस पर अमल करने की योजना बनाई जा रही है।